S. No.	Name	(As on 31.3.1991) (Rs./Lakhs) Assets	Liabilities (Excluding Share Capital)
1	2	3	4
6.	National Textile Corpn. (M.P.), Indore	27578.91	24221.94
7.	National Textile Corpn. (SM), Bombay	48102.43	43558.82

जापान के साथ द्विपक्षीय संबंध

*432. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटूभाई पटेल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ख) इस संबंध में जापान की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) भारत ने उच्च स्तर पर यात्राओं के आदान-प्रदान, जापान के साथ आर्थिक सहयोग की गति तेज करने के माध्यम से तथा सांस्कृतिक और शैक्षिक अन्योन्य-क्रियाओं के माध्यम से जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और घनिष्ठ बनाने के प्रयास किए हैं। विदेश मंत्री ने जनवरी, 1992 में जापान की यात्रा की थी और जापान के विदेश मंत्री के साथ उपयोगी और रचनात्मक बातचीत की थी। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री और जापान के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने जापान की यात्रा करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह वर्ष भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना और स्थायी शांति तथा भाई-चारे से संबंद्ध भारत — जापान सन्धि हस्ताक्षर होने की 40वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है।

(ख) जापान की सरकार ने कहा है कि उनकी यह इच्छा है भारत के साथ जापान के संबंधों को और घनिष्ठ तथा व्यापक बनाया जाए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक उदारता की नीतियों की सराहना की है। जनवरी, 1992 में जापान का एक उच्च स्तरीय आर्थिक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा गया था ताकि भारत और जापान के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने और पारस्परिक समझबूझ को घनिष्ठ करने के अवसर बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा सके।

*433. [*Transferred to the 31st March*, 1992]

Election Commission's recommendations on electoral reforms

*434. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Election Commission has recommended to the Government that candidates found violating the model code of conduct and guilty of corrupt practices should be automatically disqualified for a period of six years from contesting elections;

(b) if so, the reaction of the Government in this regard;

(c) whether in view of numerous incidents of booth capturing, Government propose to examine the recommendations for implementation; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Government is undertaking an indepth study of the entire gamut of electoral reforms and the proposals received from the Election Commission are being considered as part of the study.

उत्तर प्रदेश में आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास

*435. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आदिवासी और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों के विकास की कुछ योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में पांच अनुसूचित जनजातियां हैं और उनके निवास के क्षेत्र हैं: अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और

उत्तरकाशी जिलों में भोटिया; बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों में बुक्सा; देहरादून जिले में जोनसरी, पिथौरागढ़ जिले में राजी; और बहराइच, गोण्डा, खेरी, महाराजगंज तथा नैनीताल जिलों में थारू।

जनजातीय उप-योजना कार्यनीति, विकास के सभी क्षेत्रकों को शामिल करते हुए लखीमपुर-खेरी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, जनजातीय बाहुल्य गोण्डा क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां राजी तथा बुक्सा आदिवासी जनजातियों के प्राचीन समूह रहते हैं प्रचलन में है। इसके अलावा राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में, पांच जनजातीय विकास परियोजनाओं के तहत फैले हुए जनजातीय समूहों के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। पिथौरागढ़ की राजी आदिवासी जाति के समग्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक माइक्रो-योजना तैयार की गई है।

Facilities to Female Weavers in Rural Areas

*436. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what steps have been taken to provide facilities to female weavers and women engaged in handicrafts and handlooms in rural areas for improvement and development of their skill;

(b) what are the training facilities given to women for promoting the handloom and handicrafts industries; and

(c) what financial assistance was given during the last five years to the rural women engaged with the work of weaving, knitting, tailoring, embroidery, cane and bamboo works, handicrafts and handloom etc. in rural and hilly areas of the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) 23 Weavers Service Centres provide short-term training course of four months duration to weavers who are trained in improved method of weaving, dyeing and designing and for this each weaver is entitled to a stipend of Rs. 250/- per month. The Weavers Service Centres also undertake decentralised training of weavers at the door step of the weaver for which a sum of Rs. 350/- per month is paid. These training facilities are available to all weavers including women. On the handicrafts side, there are 515 training centres for imparting training in Carpet, Metal-ware, Cane and Bamboo, printing of textiles and misc. crafts. Moreover, there are 35 departmental training centres for cane and Bamboo crafts. This facility is extended to all weavers, including women.

(c) Government of India does not maintain separate statistics of expenditure incurred on training in handloom weaving and handicrafts for women. An estimated sum of Rs. 2712 lakhs has been spent on establishment of Weavers Service Centres which includes the amount spent for training of weavers. An estimated sum of Rs. 4450 lakhs was spent for training in handicrafts.

Discontinuance of Central Aid to Special Category States

*437. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have discontinued giving aid to special category States;

(b) whether it is also a fact that this has adversely affected the development plan of these States;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to resume aid to these States; and

(e) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) to (e) Central assistance is made available to meet the development requirements of the Special Category States, as per approved Plan outlay, based on the availability of total funds. About 30 per cent of formula based total funds available for allocation are set aside for the Plan assistance of these States. Since their share in total population of the country is much lower, per capita assistance going to these States is substantially higher than the average of non-Special Category States. In the past, non-plan gap was also covered by Central